उद्योगों को सब्सिडी में 1200 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगी विकास को रफ्तार

अनुपूरक बजट : अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के लिए 900 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। अनुपूरक बजट में उद्योगों के लिए करीब 7566 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1442 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 6124 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के रूप में हैं। इसमें से लगभग 6400 करोड़ रुपये गंगा एक्सप्रेसवे को दिए जाएंगे। करीब 1200 करोड़ रुपये उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में रखे गए हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपये और नई औद्योगिक नीति के लिए 275 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

गंगा एक्सप्रेसवे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यही वजह है कि अनुपूरक बजट का आधा हिस्सा इसे दिया गया है। 593 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे को अगले साल जनवरी में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले शुरु कर दिया जाएगा। 12 जिलों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे उद्योगों को नई रफ्तार देगा। यही वजह है कि बजट में 5664 करोड़ रुपये वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंड) के रूप में और 407 करोड़ रुपये जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में रखे गए हैं। बजट की कमी पर वीजीएफ फंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दिया जाता है।

बंद कताई मिलों में नई इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ : बजट में सहकारी कताई मिल, उप्र. स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, उप्र. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, उप्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड पर 193 करोड़ रुपये की देनदारी के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इससे बंद पड़ी इन मिलों में नई इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड कानपुर से संबद्ध बंद पड़ी मेजा, बांदा और रसड़ा (बलिया) यार्न मिलों की 324.63 एकड़ भूमि, यूपी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड कानपुर से संबद्ध रायबरेली, बाराबंकी, मऊनाथ भंजन कताई मिलों की 212.79 एकड़ भूमि, राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड कानपुर से संबद्ध झांसी, संडीला, मेरठ वस्त्र मिल की 221 एकड़ भूमि और सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड से संबद्ध कंपिल (फर्रुखाबाद), बुलंदशहर, फतेहपुर, बहेड़ी (बरेली), अमरोहा, नगीना (बिजनौर), बहादुरगंज (गाजीपुर), मगहर (संत कबीर नगर), महमूदाबाद (सीतापुर) और मउआईमा (प्रयागराज) की 705 एकड़ भूमि मिलों की बंदी से बेकार पड़ी है। ये जमीन कुल 1500 एकड़ है।

275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई नई औद्योगिक नीति के लिए

इन मदों में दिया गया बजट

- शासकीय कार्यालयों को हाईटेक करने के लिए 99.27 लाख।
- भूमि प्रकोष्ठ व स्थापना सॉफ्टवेयर प्रणाली के लिए 16.5 लाख।
- ग्राम पंचायतों को वाईफाई कनेक्शन से जोड़ने और 5 एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) के लिए 46.33 करोड़।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति के लिए 4.78 करोड़।
- कताई, स्पिनिंग और वस्त्र निगम की मिलों की देनदारियों के भुगतान के लिए 193 करोड़।
- यूपी डाटा सेंटर नीति के लिए 1.88 करोड़।
- एकमुश्त पुनर्वासन नीति-2015 के लिए 20 करोड़।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के क्रियान्वयन के लिए 900 करोड़।
- नई औद्योगिक नीति के लिए 275 करोड़।
- सरकारी दफ्तरों को ई ऑफिस बनाने के लिए 11.96 करोड़।
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के लिए 40 करोड़।

ऊर्जा विभाग को मिले 2000 करोड़ रुपये

अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इसे किसानों और कमजोर वर्गों को दी जाने वाली राहत में खर्च किया जाएगा। रिहंद और ओबरा बांध सुधार परियोजना के लिए 4.2 करोड़, आरडीएसएस योजना के तहत कराए जा रहे कामों के लिए 500 करोड़, राजस्व अनुदान के तहत 983.92 करोड़ दिए गए हैं। टैरिफ सब्सिडी के तहत 511.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बजट प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।

10 अरब से खरीदी जाएंगी रोडवेज बसें

अनुपूरक बजट में परिवहन विभाग के लिए 10 अरब 64 लाख का प्रावधान किया गया है। इसमें कुंभ मेला के लिए डीजल बसें खरीदने पर 10 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह पांच करोड़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के लिए और 64 लाख रुपये स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान के लिए प्रावधान किया गया है।